आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 20.06.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य में लगभग छह हजार कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए 289 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी।
- कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल शहर में सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
- मानसून के दौरान राहत व बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए सभी ज़िलों में 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।

प्रोत्साहन राशि वितरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत दो हजार चार सौ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना ळें

प्रोत्साहन राशि

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत उत्तराखंड में लगभग छह हजार कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है और उत्तराखंड सरकार युवाओं को सशक्त, सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री धामी ने युवाओं से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं, पेयजल परियोजनाओं, यातायात सुधार, आपदा प्रबंधन और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए 289 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के लिए 75 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त, देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार और प्रमुख चौराहों के आधुनिकीकरण के लिए 33 करोड़ 45 लाख रुपये तथा सहसपुर और शंकरपुर–हुकुमतपुर पेयजल योजनाओं के लिए कुल 40 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित पिथौरागढ़ जिले के 78 परिवारों के पुनर्वास के लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपये तथा वन्यजीव जनित क्षति के मामलों के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा विश्व बैंक सहायतित यू–प्रिपेयर परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है। वहीं, खटीमा, चंपावत, हरिद्वार और अन्य क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

भूमिगत विद्युत लाइन

श्रीनगर गढ़वाल शहर में सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शहर में बिजली के खंभों पर झूलते तारों से लोगों को राहत मिलेगी और शहर के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रीनगर में विद्युत समस्याओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में डॉ. रावत ने शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी भवनों, विद्यालयों और अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

बैठक में उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के उफरैंखाल में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की जानकारी देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के बड़े हिस्से में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
डॉ. रावत ने अधिकारियों को विभिन्न गांवों में जर्जर विद्युत पोलों को बदलने, आवश्यकता के अनुसार पोलों की शिफ्टिंग करने, पुराने ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नए ट्रांसफार्मर लगाने तथा विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के निर्देश भी दिए।

मॉक ड्रिल

मानसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए राज्य के सभी ज़िलों में 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में प्रदेशभर के करीब 70 स्थानों पर एक साथ अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में ओरिएंटेशन एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जनपदों को मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट–

इस बार मॉक ड्रिल केवल नए स्थानों पर आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल से पहले 30 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपदों द्वारा संसाधनों की उपलब्धता, उनकी तैनाती और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मॉक ड्रिल घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के अंतर्गत आयोजित की जाएगी।

अभ्यास के दौरान राहत शिविरों की स्थापना, बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्थाओं को वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाएगा। साथ ही सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सैनिकों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मॉक ड्रिल में जलभराव, भूस्खलन, स्कूलों से बच्चों की सुरक्षित निकासी, कटे हुए क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाने, जल विद्युत परियोजनाओं से पानी छोड़े जाने पर अलर्ट जारी करने तथा हेलीकॉप्टर के माध्यम से फंसे लोगों के रेस्क्यू जैसे विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित राज्य की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना की डीपीआर को स्वीकृति देने तथा इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल कर इसकी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर–बागेश्वर रेल लाइन परियोजना की डीपीआर को भी शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया गया।

बैठक में हरिद्वार–देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना पर भी चर्चा हुई। रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि हरिद्वार–मोतीचूर रेल लाइन दोहरीकरण को स्वीकृति मिल चुकी है और यह कार्य दो चरणों में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अतिक्रमण हटाने में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मेरठ–ऋषिकेश आर.आर.टी.एस कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा हुई। ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक प्रस्तावित 78 किलोमीटर लंबे संरेखण की डीपीआर तैयार किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

तैयारियां / समीक्षा

कुंभ मेला–2027 की तैयारियों के तहत रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मेला प्रशासन, रेलवे और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं के आवागमन, रेलवे संचालन, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बैठक में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारतीय रेलवे मेला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करेगा। उन्होंने प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान बढ़ने वाले यात्री दबाव को देखते हुए विशेष ट्रेनों के संचालन, अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रेलवे स्टेशनों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त क्षमता वाले होल्डिंग एरिया विकसित करने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षित और त्वरित निकासी के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। साथ ही सीसीटीवी निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना आदान–प्रदान की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल